ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक मंडल को स्विस सरकार ने पुनर्स्थापित किया

निदेशक मंडल के खिलाफ सभी आरोप सिद्ध गलत हुए। स्विस सरकार और प्रशासन ने निदेशकों को सभी आरोपों से बरी किया और उन्होंने पुष्टि की कि उक्त फाउंडेशन ओशो के इरादों के अनुसार अपना काम कर रही है।

ज्यूरिख, 13 सितंबर, 2014: 12 सितंबर 2014 के एक प्रभावशाली और निर्णायक शब्दों में लिखे हुए निर्णय में स्विस सरकार के अधिकारियों ने (जिसे ईडीआई कहते हैं) एक पूर्व आदेश को उलट दिया जिसके अनुसार ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक मंडल को अस्थायी रूप से रॉबर्ट डोएश उर्फ "स्वामी रामतीर्थ" द्वारा किए गए आरोपों के बाद निलंबित कर दिया था। उन्होंने पाया कि वे आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं ।(हमने आपको जून महीने में युरोपियन ट्रेडमार्क केस के बारे में सूचित किया था जो जुरिख फाउंडेशन के पक्ष में था; और उसके बाद रामतीर्थ के नये हमले के बारे में भी जानकारी दी थी।)

इस 12 सितम्बर के फैसले के परिणाम स्वरूप फाउंडेशन के पांच निदेशकों को दुनिया भर में ओशो की रचनाओं के सभी प्रकाशन और अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस गतिविधियों सहित ओ आइ एफ की सभी दैनंदिन गतिविधियों के पूर्ण नियंत्रण के साथ स्विस सरकार ने बहाल कर दिया है।

प्रस्तुत है स्विस अधिकारियों के निर्णय के कुछ प्रासंगिक अंश का अनुवाद:

"जैसा कि शीघ्र ही उपर्युक्त आदेश की शुरुआत के बाद और प्रशासक द्वारा अपना काम शुरू करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि धन का अनुचित उपयोग, या फाउंडेशन की समितियों द्वारा फाउंडेशन के अवैध विनियोग के बारे में नियामक शिकायत में उठाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी [...] विशेष रूप से, जहां तक आपराधिक कानून का सवाल है, जैसा कि बार-बार शिकायतकर्ता द्वारा संकेत दिया गया था, फाउंडेशन की समितियों द्वारा किसी भी ऐसे आचरण का कोई सबूत प्रासंगिक नहीं होगा ....

"ईडीआई [गृह मंत्रालय के संघीय विभाग], व्यवस्थापक का व्यापक कार्य, और स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा आंतरिक रिश्तों के प्रकटीकरण ने यह दिखाया है कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ओशो की देशना और संदेश फैलाने के अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल हुआ है। सीधे प्रकाशकों के साथ "प्रकाशन करार" के माध्यम से तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से भारतीय प्रकाशकों के साथ किताबें प्रकाशित करने के करार किए गए हैं ।

"शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य आरोप, कि कंपनियों का एक सोद्देश्य, वैश्विक, भ्रामक नेटवर्क स्थापित किया गया था ताकि इस तरह उत्तरदाताओं के हक में संपत्ति को खींचा जाए, इसमें कोई सत्यता साबित नहीं हुई है ।

आधिकारिक ज्यूरिख शिकायत रामतीर्थ द्वारा अपने व्यक्तिगत नाम में दायर की गई थी, जबकि दो अन्य शिकायतकर्ताओं ने सरकारी कागजात में उनके नाम गुमनाम रखने के लिए सरकार के अधिकारियों को कहा था लेकिन बाद में इंटरनेट पर, सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वे इस कार्रवाई का हिस्सा हैं। स्विस सरकार को विदित हुआ है कि रामतीर्थ इस प्रयास में अकेले काम नहीं कर रहे थे अपितु वे एक समूह के लिए अग्रिम चेहरा थे जो लोग 14 साल तक ओशो के कार्य (कॉपीराइट और ट्रेडमार्क) की बौद्धिक संपत्ति पर हमला करते रहे हैं।

ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशकों द्वारा रामतीर्थ के हमले के जवाब में कई प्रस्तुतियाँ, जिनमें से कुछ अत्यधिक सम्मानित कानून फर्मों द्वारा बनाई गई थीं, पेश की गईं । इसीलिए स्विस सरकार को पिछले दशक में डोएश के तरीकों, इतिहास और भागीदारी की पृष्ठभूमि में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिली ।

"वर्ष 2000 से, शिकायतकर्ता रामतीर्थ और घनिष्ठता से संबंधित अन्य पक्षों ने विभिन्न देशों में प्रतिवादी 1 [ओआइएफ] के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य था, "ओशो इंटरंनैशनल फाउंडेशन" के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को हटाना। शिकायतकर्ता खुद जाहिरा तौर पर विभिन्न उद्यमों के माध्यम के द्वारा ओशो के नाम तहत आकर्षक व्यापार के मामलों का आयोजन करता है। ईडीआई इस

पृष्ठभूमि से अनजान था; 20 मई, 2014, की पर्यवेक्षी शिकायत के अनुभाग "प्रेरणा और शिकायतकर्ता की वैधता" में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। अत: ऐसी छवि बनाई गई थी कि शिकायतकर्ता एक व्यक्ति के रूप में काम कर रहा है और इच्छुक पार्टियों या प्रतिवादी 1 के प्रतियोगियों के एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं।"

आरोप का जवाब देने के लिए जो वास्तविक सबूत प्रस्तुत किया गया था उसकी कार्यवाही के दौरान स्विस अधिकारियों को अधिक गहराई से पता चला कि रामतीर्थ ने निदेशक मंडल के खिलाफ अपनी शिकायत में न केवल भ्रामक और झूठी जानकारी प्रदान की थी बल्कि उन्होंने अपने अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रखी थी कि फाउंडेशन और ओशो के काम के खिलाफ कानूनी हमलों को भड़काने में उनकी क्या भागीदारी थी। उदाहरण के लिए, रामतीर्थ ने स्विस अधिकारियों को सूचित नहीं किया कि वह हाल ही में हुए फाउंडेशन के यूरोपीय ट्रेडमार्क मुकदमे में ओशो के काम पर कानूनी और अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संरक्षण पर हमला करने के पीछे थे जबकि इस व्यवस्था को ओशो ने व्यक्तिगत तौर पर बनाया था । उनकी इन "भूलों ने" कानूनी कार्रवाई की दिशा बदल दी।

"12 अगस्त, 2014 शिकायत का प्रतिसंवेदन केवल 2-6 उत्तरदाताओं के खिलाफ उठाए गए आरोपों और इल्ज़ामों को खारिज नहीं करता, वरन अतिरिक्त वक्तव्य खुद शिकायतकर्ता को एक प्रतिकूल प्रकाश में पेश करता है। "

यद्यपि स्विस सरकार शुरू में हर शिकायत को गंभीरता से लेने के लिए कानून द्वारा बाध्य था, यह हर किसी को जल्दी स्पष्ट हो गया कि सभी आरोप झूठे थे और बिना किसी भी सबूत के दायर किए गए थे, और इसके अलावा फाउंडेशन और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए थे।

अपनी गलतियां छिपाने के परिणाम स्वरूप सरकार भी रामतीर्थ की शिकायत की वैधता का शुरूआत से पुनरमूल्यांकन करेगी। दूसरे शब्दों में, वह जांच जरेगी कि क्या रामतीर्थ को यह कार्रवाई करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए था।

"2 जून 2014 के आदेश में, शिकायतकर्ता के बारे में इस ढांचे के भीतर इस वैधता की पुष्टि की गई थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान फ़ाइल की स्थिति के कारण [...] यह सवाल फिर से खुल गया । शिकायतकर्ता की वैधता का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान शिकायत में अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित किया जाएगा। "

स्विस अधिकारियों को अपने निर्णय में बोर्ड व्यवस्थापक श्री एंड्रियास केलर, जो कि स्विस सरकार द्वारा निलंबन के दौरान उन्हें अस्थायी रूप से फाउंडेशन के कामकाज की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए थे, से भी मजबूत समर्थन प्राप्त था। पिछले तीन महीनों में श्री केलर ने फाउंडेशन के प्रकाशन और लाइसेंसिंग के कामकाज और फाउंडेशन की अन्य गतिविधियों को समर्थन दिया ताकि फाउंडेशन को होनेवाले अतिरिक्त नुकसान को रोका जा सके।

"उनकी 8 सितम्बर 2014 विचार बयान में प्रशासक ने भी निष्कर्ष निकाला है कि विशेष रूप से 2-6 नं के उत्तरदाताओं पर लगे शिकायतकर्ता के आरोप, कि उन्होंने यह काम किसी आत्म संवर्धन के लिया किया है, निरर्थक हैं।

व्यवस्थापक बताते हैं कि उत्तरदाता 2-6 ने उनके बारे में की गई हर शिकायत के संबंध में विस्तृत टिप्पणी दी और कहा कि उनके विचार में संबंधित स्पष्टीकरण विश्वसनीय हैं। यह विशेष रूप से लागू होता है जहां तक विकसित कंपनी की संरचना का सवाल है [...] जो मुख्य रूप से कर कारणों के लिए बनाया गया था। तथापि, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन खुद एक कर मुक्त इकाई नहीं है; उसने कभी भी केंटनल टैक्स प्राधिकरण को कर में छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए इसमें जरा भी सचाई नहीं है कि ओशो इंटरनेशनल

फाउंडेशन को कर में छूट दी गई थी जैसा कि शिकायतकर्ता ने आंशिक रूप से और सार्वजनिक रूप से भी बार-बार दावा किया है (Oshonews ऑनलाइन Magazine1 में 28 अगस्त 2014 को एक रिपोर्ट में उदाहरण के लिए,)। "

आपकी जानकारी के लिए, उल्लेखित OSHOnews.com वेब साइट एक समूह "ओशो वर्ल्ड" के नियंत्रण के अधीन एक संस्था है जो खुद को "ओशो के मित्र (फ्रैण्ड्स ऑफ ओशो) " कहते हैं। यह साइट एक स्वतंत्र समाचार साइट होने का दिखावा करती है, लेकिन अक्सर विकृत जानकारी प्रकाशित करती है जो ओशो के आदेश और अनुरोध के बिलकुल विपरीत है; और जो ज्यूरिख और पुणे ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन पर हमला करने का एक साधन है। मौजूदा मामले में इस साइट / न्यूजलेटर ने डोएश के बदनामी करनेवाले आरोप और विकृत प्रस्तुतियों को प्रकाशित किया जिसके संदर्भ में स्विस सरकार ने ऊपर के पैरा में बात की है।

रामतीर्थ ने न केवल बोर्ड के सदस्यों पर पैसे चुराने का आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी रॉयल्टी का हिसाब कर ये लोग ओशो की कृतियों से पर्याप्त पैसा नहीं बना रहे हैं। फाउंडेशन ने कई सालों से दुनिया भर में सभी प्रकाशकों के लिए लाइसेंस करारों को जारी किया है। उन्होंने ऐसा आकर्षक और उचित वित्तीय शर्तों पर इसलिए

किया है ताकि ओशो की कृतियां जल्द से जल्द कई देशों और भाषाओं में उपलब्ध हो सकें । रामतीर्थ ने दावा किया है कि फाउंडेशन को ओशो की कृतियों से अधिक पैसा बनाना चाहिए । स्विस सरकार ने निम्नलिखित तरीके से इस दावे को संबोधित किया:

"यह तथ्य कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ओशो की कृतियों के कॉपीराइट के माध्यम से बहुत कम राजस्व ले रहे हैं, इससे पता चलता है कि फाउंडेशन का उद्देश्य उसके संस्थापक की इच्छानुसार काम करना है। जिसके अनुसार मास्टर की कृतियां सस्ती कीमत पर बेची जानी चाहिए। इस प्रकार, आर्थिक सफलता का हेतु उनकी रचनाओं के उद्देश्य से निकाल देनी चाहिए।

स्विस सरकार उनके विस्तृत विश्लेषण और उनके निर्णय का तर्क इस तरह समाप्त करती है:

"इन आधारों पर यह आदेश दिया है:

2 जून के आदेश के अनुसार ओशो इंटरनेशनल

ईडीआई द्वारा 2014 ओशो इंटरनैशनल फाउंडेशन के संपूर्ण निदेशक बोर्ड के निलंबन के फरमान को निरस्त किया गया है। फाउंडेशन के निम्न व्यक्तियों को उनके कार्यालयों और कार्यों में बहाल किया जा रहा है। [...]

माइकल ओबर्न, (2013 के बाद से: माइकल बर्न) बोर्ड के अध्यक्ष; जॉन एंड्रयूज, उपाध्यक्ष; डार्सी ओबर्न, बोर्ड के सदस्य; क्लाउस स्टीग, बोर्ड के सदस्य; रुडोल्फ कोचर, बोर्ड के सदस्य।

2 जून, 2014 के आदेश के माध्यम से निदेशक मंडल पर लगाए गए ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की संपत्ति की उपलब्धता के लिए निषेध को निरस्त किया गया है। "

इस पर ध्यान दें कि स्विस अधिकारियों का यह फैसला इस साल के अक्टूबर 13 तक अपील करने तक लागू है। जैसा कि हमने अब तक देखा है, रामतीर्थ और उनके समूह द्वारा ओशो के काम की रक्षा करनेवालों को लेकर इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी, जिस तरह उन्होंने यूरोपीय ट्रेडमार्क फैसले के खिलाफ पहले से ही किया है।

सस्नेह,

इनर सर्कल